

मुख्यमंत्री भजनलाल ने आमेर में उपराष्ट्रपति वैंस का स्वागत किया

वैंस व उनके परिवार ने ऐतिहासिक आमेर किले का भ्रमण किया

■ **आमेर पहुँचने पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जैम्स वैंस व उनके परिवार का ढोल-नगाड़ों व सजे हुए हाथियों के साथ राजस्थानी परम्परा से स्वागत हुआ। लोक कलाकारों ने पारम्परिक वेशभूषा में कालबेलिया व कच्छी घोड़ी नृत्य प्रस्तुत किया।**



अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस जयपुर यात्रा के दौरान आमेर किला देखने गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उनके साथ थे।

जयपुर, 22 अप्रैल। संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वैंस की जयपुर यात्रा के दूसरे दिन आमेर किले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनका आत्मीयतापूर्वक स्वागत किया।

मुख्यमंत्री ने वौस को बुके भेंट कर उनके सुखद प्रवास के लिए शुभकामनाएं दीं और उन्हें राजस्थान की बहुरंगी संस्कृति एवं आतिथ्य सत्कार परंपरा के बारे में जानकारी दी। वैंस, उनकी धर्मपत्नी उषा वैंस एवं बच्चे मंगलवार सुबह आमेर किले का भ्रमण करने पहुंचे। यहां उनका ढोल-नगाड़ों और सजे हुए हाथियों के साथ राजस्थानी परंपरा

से स्वागत किया गया। इस दौरान लोक कलाकारों ने पारंपरिक वेश-भूषा में कालबेलिया व कच्छी घोड़ी नृत्य प्रस्तुत किया। राजस्थानी कला-संस्कृति की मनोहारी प्रस्तुतियों से उपराष्ट्रपति वैंस और उनके परिजन अभिभूत नजर आए। इसके बाद वे आमेर किले का भ्रमण कर राजस्थान की ऐतिहासिक स्थापत्य धरोहर से रूबरू हुए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी उपस्थित रही। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति वैंस सोमवार रात्रि सपरिवार जयपुर पहुंचे थे। वैंस 24 अप्रैल को प्रातः अमेरिका के लिए प्रस्थान करेंगे।

30 जून से शुरू होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा

नई दिल्ली, 22 अप्रैल। कैलाश मानसरोवर यात्रा पांच साल बाद इस वर्ष 30 जून से शुरू होगी जिसका मार्ग उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में 17 हजार फुट की ऊंचाई पर स्थित लिपुलेख दर्रे से होगा। यहां सोमवार को जारी विज्ञप्त में यह जानकारी दी। सरकारी विज्ञप्त के अनुसार, हर वर्ष आयोजित होने वाली यह यात्रा 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दी गई थी और उसके बाद से यह संचालित नहीं हो पाई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विशेष प्रयासों से इस वर्ष यह संभव हो पायी है। विज्ञप्त के अनुसार उत्तराखंड सरकार एवं भारतीय विदेश

■ **यात्रा में 30 जून से 22 अगस्त के बीच 50-50 श्रद्धालुओं के 5 दल कैलाश मानसरोवर जाएंगे।**

मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित होने वाली इस यात्रा के संबंध में सोमवार को नयी दिल्ली में एक बैठक की गयी, जिसमें इसके संचालन का जिम्मा कुमाऊँ मंडल विकास निगम को सौंपा गया।

यह यात्रा दिल्ली से 30 जून को शुरू होगी जिसमें 50-50 व्यक्तियों के कुल पांच दल होंगे और इस प्रकार इस यात्रा में ढाई सौ श्रद्धालु शामिल होंगे।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मुसलमान, सरकार के साथ खड़े हैं।” उन्होंने चेतावनी दी कि यह कदम धार्मिक अधिकारों व संस्थान की रक्षा के लिए समुदाय के संघर्ष को कमजोर कर सकता है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का एजेंडा सुप्रीम कोर्ट को भ्रमित करने और मुस्लिम समुदाय में फूट डालने का है।

वक्फ कानून, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी रोक लगा दी है, की विभिन्न वर्गों ने कड़ी आलोचना की है, जिसमें राजनैतिक दल, मुस्लिम संगठन तथा कानूनी विशेषज्ञ शामिल हैं। इनका कहना है कि इस नए कानून में ऐसे प्रावधान हैं, जो मुसलमानों की धार्मिक एवं चैरिटेबल प्रॉपर्टी पर उनका नियंत्रण कमजोर कर सकते हैं। गत शनिवार को हैदराबाद के मुसलमानों का भारी विरोध

प्रदर्शन हुआ, जिसमें कई मुस्लिम संगठनों, विद्वानों व राजनैतिक दलों ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने मुसलमानों को बांटने की सरकारी नीति की आलोचना की। रैली में बोलते हुए ओवैसी की पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बोहरा समाज के नेताओं की अपने पूर्व वादे से मुकरने के लिए आलोचना की। उन्होंने कहा, जेपीसी में बोहरा समाज ने साफ कहा था कि वे वक्फ बिल का समर्थन नहीं करेंगे। अब क्या बदल गया। नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी बोहरा समाज को गुमराह कर रहे हैं। बोहरा समाज अपने सुगठित ढांचे व अनुशासन के लिए जाना जाता है, उसका केन्द्र की सरकारों के साथ उदासीन या सहयोगी व्यवहार रहा है, लेकिन वक्फ एक्ट का सार्वजनिक समर्थन करने के कारण वे मुसलमानों के विरोध का

सामना कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि वक्फ कानून में संशोधन वक्फ सम्पत्ति के प्रशासन में पारदर्शिता लाएगा तथा इसका आधुनिकीकरण करेगा है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि नया कानून वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता खत्म कर इसका कंट्रोल सरकार को दे देगा। सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई के लिए तैयार है। ऐसे में कानून विशेषज्ञों को लगता है कि बोहरा समुदाय की याचिका सुनवाई को जटिल कर देगी और मुस्लिम समुदाय में विभाजन कर देगी। सरकार इसके जरिए संशोधन को न्यायोचित ठहरा सकती है। तनाव बढ़ रहा है और राजनैतिक दांव भी बहुत ऊंचे हैं, क्योंकि यह एक्ट मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों और केन्द्र सरकार से उनके रिश्ते के लिए निर्णायक होगा।

पहलगाम में बड़ा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पर्यटकों को निशाना बनाकर आतंकी जम्मू-कश्मीर में सैलानियों के प्रवेश को रोकना चाहते हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। मोदी ने एक्स पर कहा, मैं जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूँ। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएँ। प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा, इस जघन्य कृत्य के पीछे जो लोग हैं, उन्हें न्याय के कठघरे में लाया जाएगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनका नापाक एजेंडा कभी सफल नहीं होगा। आतंकवाद से लड़ने का हमारा संकल्प अडिग है तथा यह और भी मजबूत होगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, आतंकवादियों ने पर्यटकों के एक समूह पर गोलीबारी की, जिसमें कई लोग घायल हो गए। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि आठ घायलों को पहलगाम में एक अस्पताल ले जाया गया। बाद में दो लोगों को गंभीर हालत में श्रीनगर अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया।

दिल्ली हाईकोर्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पतंजलि के शरबत की लॉन्चिंग की थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा था कि एक कंपनी शरबत बनाती है। उससे जो पैसा मिलता है, उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। बाबा रामदेव ने कहा था कि जैसे लव जिहाद और वोट जिहाद चल रहा है, वैसे ही शरबत जिहाद भी चल रहा है। इसके खिलाफ रूह अफजा शरबत बनाने वाली कंपनी हमदर्द ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कंपनी की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दलीलें दीं। रोहतगी ने कहा कि यह घम के नाम पर हमला है।

उपराष्ट्रपति वैंस ने भारत-अमेरिका ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उत्पादों की अधिक खरीद करनी चाहिए और फिर “रक्षा उत्पादन” में परस्पर सहयोग करना चाहिए। वैंस ने दावा किया कि अमेरिकी रक्षा उत्पाद “सबसे बेहतरीन” हैं और इन्हें भारत के लोगों और देश की सुरक्षा में मदद करनी चाहिए। अमेरिका यह जानता है कि भारत-रूस से भी रक्षा उपकरणों की खरीद करता है।

यूक्रेन में चल रहे युद्ध के संदर्भ में, रूस अक्सर अपनी महत्वपूर्ण रक्षा सामग्री की आपूर्ति बनाए रखने में असमर्थ है, जिससे भारत को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विविध रक्षा खरीद भारत को रक्षा आपूर्ति शृंखलाओं में रणनीतिक कमियों को दूर करने में मदद कर सकती है।

वैंस ने विशेष रूप से अत्याधुनिक एफ-35 विमानों की भारत द्वारा खरीद का उल्लेख किया है, जो युद्ध के सबसे घातक हथियारों में से एक माने जाते हैं। अब तक इन विमानों की बिक्री पर गंभीर प्रतिबंध थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका अब इन्हें भारत को बेचना चाहता है। भारत को इन विमानों की खरीद में अरबों डॉलर तक खर्च करना पड़ सकता है।

इसके अलावा, चीन की अनुचित व्यापार प्रैक्टिस पर परोक्ष टिप्पणी करते हुए, वैंस ने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच साझा सहयोग अन्यायपूर्ण तरीकों को मात देने में मदद कर सकता है, जो बाजार में वास्तविक खिलाड़ियों के प्रवेश को

अवरुद्ध करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ऊर्जा उद्योग में भारत और अमेरिका के सहयोग की बात कर रहा है, खासकर भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस और तेल के दोहन को लेकर।

अमेरिका का कहना है कि उसके पास ऐसी तकनीकें हैं, जो ऊर्जा क्षेत्र के विकास में भारत को मदद कर सकती हैं। वैंस ने यह भी कहा कि अमेरिका इस तरह के ऊर्जा-कुशल उत्पादन तरीकों को प्राप्त करने में भारत के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। इस प्रकार के सहयोग से तेज विकास के साथ कम ऊर्जा का उपयोग होगा। इसके अतिरिक्त, अमेरिका फार्मास्यूटिकल्स और रसायन क्षेत्र में भी भारत के साथ काम करना चाहता है। अब तक फार्मा उत्पादों की रैसिप्रोकल टैरिफ व्यवस्था में शामिल नहीं किया गया था। हालांकि, अगर इन्हें भी इस व्यवस्था में लाया जाता है, तो भारत को भारी नुकसान हो सकता है। भारत अमेरिका को फार्मा उत्पादों का बड़ा निर्यात करता है, जो मुख्य रूप से भारतीय उद्योग द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन ये चीन से आयातित मूल फार्मास्यूटिकल सामग्री (इनफुट) से बनते हैं। अगर चीन इस सामान की आपूर्ति को भारत के लिए प्रतिबंधित कर देता है, तो भारतीय फार्मा उद्योग को गंभीर नुकसान हो सकता है। इसलिए, भारत के पास एक अवसर है कि वह अमेरिका के साथ फार्मास्यूटिकल सामग्री के उत्पादन के लिए एक नया आधार स्थापित करने के लिए सहयोग करे। इससे भारतीय दवा उद्योग में एक

नई क्रांति आ सकती है।

इस क्षेत्र में भारत को सतर्क रहना चाहिए। चीन ने चेतावनी दी है कि कोई भी देश, जो अमेरिका के साथ मिलकर चीन के व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को चुनौती देगा, उसे कड़े प्रतिबंधों और दंड का सामना करना पड़ेगा। संभावना है कि चीन अमेरिकी बाजारों के लिए फार्मा उत्पाद भेजने के लिए भारत को फार्मास्यूटिकल इनफुट की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा सकता है। वर्तमान वैश्विक व्यापार परिस्थितियों में, भारत अमेरिका-नेतृत्व वाले देशों और चीन-नेतृत्व वाले देशों के बीच एक प्रमुख और महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। यूरोपीय संघ अपने पुराने सहयोगी अमेरिका और उसके वर्तमान रुख के बीच झूल रहा है। ऐसे में, भारत, जो अमेरिका के साथ गठबंधन में है और रूस से भी पुराने संबंधों को बनाए हुए है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत को चाहिए कि वह इन अवसरों का लाभ उठाकर अपने भविष्य के लिए सबसे अनुकूल स्थिति में खुद को स्थापित करे। अब तक, भारत और अमेरिका के रिश्ते केवल औपचारिक रहे हैं। अब ऐसे अवसर सामने आ रहे हैं, जो इन रिश्तों को एक ठोस रूप दे सकते हैं। यह वार्ता का पहला चरण एक नई साझेदारी की शुरुआत हो सकता है। अगर दोनों देशों के बीच बातचीत की मौजूदा गति जारी रहती है, तो ये व्यापार वार्ताएँ अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में व्यापक सहयोग की ओर बढ़ सकती हैं।

कोटा में एक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बताया कि मृतक ने अपनी बहन को घटना से पहले उसके मोबाइल पर एक वाट्सअप किया था, जिसके बाद उसकी बहन ने ही हॉस्टल संचालक को सूचित किया। पुलिस इस मामले की विस्तृत जांच कर रही है और आत्महत्या के अन्य संभावित कारणों की जांच की जा रही है।

‘न तो संसद ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वाले पदाधिकारियों को सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के साथ बराबर दूरी कायम रखनी चाहिए। उन्होंने कहा, “प्रीसाइडिंग ऑफिसर्स की पक्षपातपूर्ण सोच उनके संवैधानिक पद की गरिमा को कम कर देता है।” उन्होंने आगे कहा: “कोई स्पीकर या चेयरमैन किसी पार्टी का प्रवक्ता के रूप में नज़र नहीं आना चाहिये।”

ग्राम पंचायतों के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जबकि छापोली ग्राम पंचायत के पुनर्गठन में इसकी अवहेलना की गई है। नई ग्राम पंचायत दस किलोमीटर दूर सोकडाला को बनाया जा रहा है, जबकि इसमें शामिल किए जा रहे कृष्ण नगर की सीमाएं भी इससे नहीं मिल रही हैं। इसके अलावा, स्थानीय विधायक ने भी कृष्ण नगर को नई ग्राम पंचायत बनाने का प्रस्ताव भेजा है। दूसरी ओर, स्थानीय जिला कलेक्टर इस संबंध में मांगी गई आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण नहीं कर रहे हैं। मामले की सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है। गौरतलब है कि राज्य में ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन और पुनःसीमांकन का काम किया जा रहा है। इसके तहत, फिलहाल नई ग्राम पंचायतों को लेकर स्थानीय स्तर पर

आपत्तियां मांगी जा रही हैं। जिला कलेक्टर की ओर से आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

‘संसद ही ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विषय में 9 उच्च न्यायालय के निर्णयों को उलट दिया था। धनखड़ ने आपातकाल को “लोकतंत्र के इतिहास में सबसे ज्यादा अंधकारपूर्ण दौर” बताया। उन्होंने कहा, “मैं इसे “सबसे ज्यादा अंधकारपूर्ण” इसलिये कहता हूँ, क्योंकि देश की सबसे ऊंची अदालत ने 9 उच्च न्यायालयों के इस निर्णय को नज़र अंदाज कर दिया था कि लोकतंत्र के मौलिक अधिकार कभी निलम्बित या स्थगित नहीं किये जा सकते।—”

MARUTI SUZUKI

DRIVE STRONG HYBRID WITH LOWER TAX.

25% ROAD TAX WAIVER ON THE GRAND VITARA STRONG HYBRID.

R17 MACHINED ALLOY WHEELS

AUTO PURIFY WITH PM2.5 DISPLAY

8-WAY DRIVER POWERED SEAT

EV MODE

6 AIRBAGS AS STANDARD

BENEFITS UP TO

₹ 1 73 100*

ADDITIONAL SCRAPPAGE BONUS AVAILABLE AGAINST VALID CERTIFICATE OF DEPOSIT.

SCAN TO CONNECT TO A SHOWROOM NEAR YOU

E-BOOK TODAY @ WWW.NEXAEXPERIENCE.COM

Contact us at

1800-200-[6392]

1800-102-[6392]

For detailed T&C kindly visit nearest dealership. Maruti Suzuki India Limited reserves the right to discontinue offers without notice and offers may vary across variants. *Offer includes consumer offer, exchange bonus and institutional or rural offer (wherever applicable) on select models/variants. Finance is at the sole discretion of financier. Scruppage offer valid for limited period only and is brought to you by Maruti Suzuki Toyota India Private Limited (a joint venture company between Maruti Suzuki India Ltd and Toyota Tsusho Group). Above offers are valid till 30th April 2025. Black glass shade on the vehicle is due to the lighting effect. Images used are for illustration purposes only. Car color may vary due to printing on paper. This extended warranty is applicable for Zeta+ and Alpha+ models of Grand Vitara.